THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI R. DHANUSHKODI ATHITHAN):(a) one Youth Hostel at Aurangabad has been functioning in Maharashtra since January, 1976.

(b) Youth Hostels provide economical, clean, comfortable and safe accommodation for youth travellers. Construction of Youth Hostel has been conceived as a Joint venture between the Central and the State Government. While the Central Government bears the cost of construction, the State Government provides fully developed land free of cost with water, electricity, approach roads, staff quarters and other aminities.

(c) and (d) The Department has sanctioned two more Youth Hostels in Maharashtra at Buldana and Navegaonkand. The State Government has not sent any formal proposal with commitment to provide fully-developed land free of cost with water, electricity, approach road etc. for the construction of Youth Hostels in Nagpur and other parts of Vidarbha region.

Conference in Ignou on Management Education

3753. SHRI AKHILESH DAS: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Indira Gandhi National Open University (IGNOU) organised a National Conference recently on networking for management education in New Delhi;

(b) the number of representatives with their respective institutions who attended the conference;

(c) whether the conference considered resource sharing and networking of resources for overall effectiveness of management education in the country; and

(d) if so, the outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA):(a) to (d) According to the information furnished by the Indira Gandhi National Open University (IGNOU), a National Conference on Networking for Management Education was organised by the School of Management Studies, IGNOU on 10-11 April, 1997 in New Delhi. Altogether 182 participants belonging to 175 different institutions attended to Conference. The participants deliberated upon exploring the possibilities and identifying strategies for networking of resources towards improving the quality of management education in the country. The idea of networking of resources with IGNOU evoked encouraging response from the participants.

सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश को विश्व बैंक की सहायता

3754. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सबके लिए शिक्षा के उद्देश्य के लिए विश्व बैंक की सहायता संबंधी कोई प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की सरकार से प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना विश्व बैंक को प्रेषित की गयी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार "उत्तर प्रदेश सभी के लिए बुनियादी शिक्षा परियोजना" के तहत पहले से ही विश्व बैंक सहायता प्राप्त कर रही है। परियोजना की कुल लागत 728.7 करोड़ रु० है जिसमें से आई० डी० ए० 165 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य क्रेडिट प्रदान करेगा जो परियोजना लागत का 87% है तथा शेष लागत

जुलाई, 1993 में विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार से और सहायता के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:—

(I) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चरण-II के तहत 15 जिलों (महराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बदायूं, खीरी, ललितपुर, पीलीभीत, बस्ती, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, सोनभद्र, देवरिया, हरदोई, बरेली, और फिरोजाबाद) को शामिल करने के लिए।

(II) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चरण-II के तहत 3 जिलों (बहराईच, बाराबंकी और रामपुर) को शामिल करना। उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना के तहत इन जिलों की आरक्षित जिलों के रूप में पहचान की गई थी परंतु अभी तक ये शामिल नहीं किए जा सके थे।

(III) अतिरिक्त शिक्षकों, नए स्कूल भवनों, अतिरिक्त शिक्षण कक्ष आदि के प्रावधान के लिए उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना के तहत 12 जिलों (गोरखपुर, वाराणसी भदोही, नैनीताल, उधम-सिंह नगर, बांदा, पौड़ीगढ़वाल, सहारनपुर, इटावा, अलीगढ़, सीतापुर और इलाहाबाद) के वास्ते विश्व बैंक से पूरक वित्त पोषण की आवश्यकता।

(ग) (I) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-II में 15 जिलों को शामिल करने के संबंध में परियोजना प्रस्ताव राज्य द्वारा तैयार कर लिए गए हैं। इस समय भारत सरकार द्वारा इनका मूल्यांकन किया जा रहा है जिसके बाद विश्व बैंक द्वारा इनका मूल्यांकन किया जाएगा। अंत में प्रस्ताव भारत सरकार की व्यय वित्त समिति के पास उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(II) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में 3 आरक्षित जिलों को शामिल करने के मुद्दे पर चरण-II के तहत निधियों की उपलब्धता के बारे में पता लगने के बाद विचार किया जाएगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चरण-II के तहत शामिल किए जाने के लिए पहचान किए गए सभी जिलों की योजनाओं के मूल्यांकन के बाद ही यह संभव होगा।

(III) उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना के 12 जिलों के लिए पूरक वित्तपोषण पर विचार करने के लिए विश्व बैंक ने मार्च, 1997 में निधि संबंधी आवश्यकता का पता लगाने के वास्ते एक पहचान मिशन का संचालन किया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार से पूरक वित्तपोषण संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया है जिसके बाद उस पर विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर के अनुरूप।

Delay in Releasing U.G.C. Funds for colleges in Assam

3755. SHRI KARNENDU BHATTACHARJEE: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the inordinate delay in releasing U.G.C. funds for Colleges in Assam, particularly Cachar College, Silchar; and

(b) if so, the remedial steps taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA):(a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

गुजरात और मध्य प्रदेश में औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

3756. **श्री दलीप सिंह जूदेव:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अधीन कितनी धनराशि आवंटित की गयी है;

(ख) उक्त कार्यक्रम के अधीन मध्य प्रदेश के विदिशा जिले और गुजरात के कच्छ जिले के लिए कितनी राशि आवंटित की गयी है;

(ग) क्या उक्त राशि का समुचित उपभोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त जिलों में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।